विचार बिन्दु

रोग, सर्प, आग और शत्रु को तुच्छ समझ कर कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। –सुभाषित

राजस्थान की गूंगी, बहरी, अंधी सरकारें

राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया एक लोकप्रिय, सफल, दूरदर्शी मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद में कोई भी मुख्यमंत्री उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। हाँ भैंरोंसिंह शेखावत अवश्य सारे प्रदेश को बाँधे रहे। कुछ अल्पकालीन ही रह सके। कुछ अहँकार से ग्रस्त रहे तो कुछ मात्र शोभाऊ। कुछ मुख्यमंत्री मात्र अपने क्षेत्र तक सीमित रहे। अधिकांश मात्र सत्ता लिप्सा एवं स्वार्थ से ग्रसित रहे। ऐसा लगता है सब काम चलाऊ सरकारें रहीं। वह तो भला हो केन्द्र का कि उसकी कुछ योजनाओं व आर्थिक सहायता से कुछ हलचल राजस्थान में बनी रही, अन्यथा सारा राजस्थान निस्तब्ध और वीराना सा ही लगता रहा।

दूरदर्शिता की बात छोड़िये, सरकारें अंधी व बहरी व गूंगी सी लगती रही हैं। सरकारी दफ्तरों में सैंकड़ों प्रकरण लम्बित रहते हैं। सामान्य जनता से लेकर सरकारी कर्मचारियों–अधिकारियों के प्रकरण वहाँ धूल चाटते रहते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजकर टरकाने, भटकाने और लटकाने की प्रवृत्ति मिटती ही नहीं है। पानी, बिजली, सड़क, सुरक्षा, सेवा प्रकरण, अनुज्ञा, भूमि, भवन, शिक्षा व चिकित्सा एवं अन्य प्रकृति के प्रकरणों में या तो निर्णय ही नहीं होता या होता है तो अनेक माह व वर्ष में। निर्णय न होने के कारण लोगों को न्यायालयों की शरण में जाना पड़ता है, वहाँ भी त्वरित न्याय दुर्लभ है और प्रकरणों का अम्बार लगा रहता है। कई कार्यालय, व सचिवालय में लोग भटकते रहते हैं। मंत्रियों के घर पर भी दरबार लगते हैं। लोग गुलामों की तरह घिघियाते रहते हैं और सामंतशाही का नया स्वरूप अहंकार के मद में डूबा आवेदक को एक तुच्छ प्राणी मानकर कभी–कभी अपनी कृपा बरसा देता है। हाँ, सिफारिश हो, मतों का मोह हो या पैसे का तो कार्य कुछ जल्दी हो जाता है। अपवाद तो हर विभाग में होते ही हैं। परंतु सामान्यतः स्थिति बद से बदतर हुई है। जब कोई सुनने वाला ही नहीं तो जवाब कौन दे। अशिक्षित ही नहीं शिक्षित लोग भी सरकारी व्यवस्था का कोई अन्य विकल्प हो तो वहाँ जाते हैं, जहाँ उनका शोषण होता है। शिक्षा व चिकित्सा हेतु मज़दूर व किसान भी निजी स्कूल व चिकित्सकालय में जाकर अपनी हैसियत से अधिक पैसा खर्च करता है, क्योंकि वहाँ कोई सुनता तो है। वहाँ भी अधिक व्यय के बाद भी गुणात्मकता हो यह आवश्यक नहीं है। भले ही कई निजी शिक्षा व चिकित्सा संस्थानों के परिणाम निराशाजनक व नकारात्मक रहते हो, वहाँ जाने की विवशता यह है कि वहाँ उनकी कोई सुनता है। केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रहने का कारण भी सरकार का बहरापन है।

ज़्यादातर बहरा और गूंगा दोनों लक्षण साथ पाये जाते हैं। सरकारें बहरी हैं तो गूंगी भी। वे कुछ बोलती ही नहीं, कुछ कहती ही नहीं। कहती है तो उन्हें वोट देने की बात, झूठे–झूठे आश्वासनों की बात, नये–नये प्रलोभनों की बात। 75 वर्ष में प्रत्येक सरकार ने कई घोषणा पत्रों की क्रियान्विति का वायदा किया परंतु उनमें से क्रियान्विति अत्यंत कम ही रहती है। अगले चुनाव में सरकारें और राजनीतिक दल नये–नये सपने दिखाकर जनता को मूर्ख बनाते हैं और निरंतर यही क्रम चलता रहा है। यदि सरकार बोले और सही बोलना चाहे तो पंचायत व पटवार सर्कल से लेकर प्रदेश के प्रत्येक स्तर की योजना व क्रियान्विति वह जनता को बताये तो ही जनता को यह पता लगे कि प्रदेश में व उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। कोई भी काम कितने समय में कितने व्यय पर हुआ और होगा यह जनता नहीं जानती। अंततोगत्वा वह कभी कितनी अवधि व कितने व्यय पर हुआ, अवधि व व्यय बढ़ते रहे तो क्यों यह भी बताया जाना चाहिये। होता यह है कि मटकी में गुड़ फूटता रहता है। जनता अँधेरे में रहती है। जनता पर व्यय भार बढ़ता रहता है, अवधि बढ़ती रहती है, साठ–गाँठ से कई कारण बता दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रियान्विति हेतु जिम्मेदार अधिकारियों व अन्य एजेन्सियों पर गुणात्मकता, वित्त एवं अवधि संबंधी क्या जिम्मेदारी गई और उनके पूर्णतः न निभाये जाने पर क्या कार्रवाई हुई, कोई नहीं बताता। यही कारण है कि कई पुल, बाँध, सड़कें व इमारतें या तो बनती ही नहीं और कई बनते ही अथवा अल्प अवधि में ढह जाती हैं। क्या कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ों अथवा अन्य राजाओं–नवाबों के समय में किये गये निर्माण आज भी मज़बूती से खड़े हैं या फिर देखरेख में लापरवाही के कारण ही क्षतिग्रस्त होते हैं। सरकारों के न बताने न बोलने के कारण ही जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये हर वर्ष आंधी–तूफान, वर्षा व बाढ़ में बह जाते हैं। एक ज्वलन्त उदाहरण स्मार्ट सिटी का है। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या होना है, क्या हुआ, कितना पैसा लगा वह समय पर हुआ कि नहीं किसी को पता नहीं है। जो हुआ वह कैसा हुआ—सफल या असफल इसका मूल्यांकन करने वाला भी कोई नहीं है। उदयपुर के सीवेज कार्य को ही लीजिये। कई जगह पाइप चोक (बंद) हो गये हैं, गंदगी बाहर बह रही है, आगे का मार्ग भी अवरुद्ध है, जनता ने कई जगह इन कारणों से सीवेज पाइपों को ही तोड़ दिया है, कहीं वह आधा–अधूरा है। सारा शहर खुदा पड़ा है और वह भी वर्षों से, मार्ग व ट्राफिक अवरुद्ध है। कोई बोलने–बताने वाला नहीं कि यह सब कब तक होगा और कैसे ठीक होगा। प्रत्येक स्तर पर सरकारी तंत्र और जन प्रतिनिधि राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाएँ बताने, समझाने व ईमानदारी से क्रियान्वित कराने में असफल रहे हैं, यही कारण है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिला है और प्रत्येक योजना की सफलता तथा गुणात्मकता का अभाव रहता है।

> **राज्य व केन्द्र सरकारों को इस देश की कई समस्याओं के प्रति अपनी कुंभकर्णी नींद को त्याग कर उस समस्या का निदान और निराकरण करने की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिये। जिला कलक्टर और एस.पी. को अपने-अपने अधिकार की कानून व्यवस्था, पार्किंग, ट्राफिक, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण, स्वच्छता व कुत्तों आदि अन्य समस्याओं पर संज्ञान, निदान व निराकरण हेतु पाबंद किया जाना चाहिये।**

यह तो प्रमाणित है कि सरकारें अंधी हैं। न्याय की तुला पर आँखों पर पट्टी बांधा व्यक्ति निष्पक्षता व ईमानदारी का सूचक है, परंतु सरकारों का अंधापन मात्र बेईमानी व भ्रष्टाचार, असफलता व अकर्मण्यता का सूचक है। क्या सरकारी नौकरशाही व सरकार के जन प्रतिनिधि यह नहीं देखते कि समाज में क्या हो रहा है। सारे राज्य की सड़कें टूटी पड़ी है। उदयपुर के नगर निगम को तो पूर्णतः असफल और अभी तक का सबसे अकर्मण्य कहा जा सकता है। कुछ माह पूर्व बनी सड़कों में भी बड़े–बड़े गड्ढे हैं। अधिकांश सड़कें कमरतोड़ व वाहनतोड़ हैं। सामुदायिक केन्द्रों की देखभाल नहीं, कहीं पानी टपक रहा है तो कहीं सीवेज ही टूटा पड़ा है। नये पार्क का उद्घाटन हाल ही केन्द्रीय रक्षा मंत्री से कराया गया परंतु अधिकांश पार्कों की दुर्दशा है। आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं की भरमार है जो दुर्घटना का कारण बनते हैं। कमोबेश यही स्थिति सारे राज्य में सुनने में आती है।

राज्य भर में पार्किंग व ट्राफिक व्यवस्था बदहाल है। क्या इसे पुलिस व प्रशासन नहीं देखता। क्या सरकारी अमला व जनप्रतिनिधि समाज के दृश्यों की अनदेखी नहीं करते। कई समस्याओं हेतु राज्य सरकार स्वयं ज़िम्मेदार है। महँगाई व बेरोज़गारी, बढ़ता आतंकवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हेतु राज्य सरकारें भी ज़िम्मेदार हैं। क्या ट्राफिक, आवागमन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़कों, सीवेज, स्वच्छता, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, सुरक्षा आदि को सरकारें खुली आँखों से देखती हैं। बताइये 75 वर्षों में राज्य में क्या–क्या नवीन हुआ है जिसने इन समस्याओं में से किसी एक का भी निदान व उपचार सरकारें कर पाई हैं। यही कहा जाना होगा कि राजस्थान राज्य की अधिकांश सरकारें कई अन्य राज्यों की तरह बहरी, गूंगी व अंधी रही हैं। अमृत महोत्सव के वर्ष 2022 तक तो सत्ताएँ समाज का विष मिटा कर अमृत प्रदान करने में असमर्थ ही रही हैं। जनता ने भी निर्वाचन में ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है। आशा करनी चाहिये कि शताब्दी वर्ष 2047 तक सरकारें सजग, सतर्क व संवेदनशील हो सकेंगी।

इस लेख की समाप्ति तक समाचार पत्रों से उच्चतम न्यायालय द्वारा श्वानों (कुत्तों) की समस्या का संज्ञान लिया है और कुत्ते का टीकाकरण एवं किसी को काटने पर पीड़ित के उपचार का ज़िम्मेदार ठहराया है। इससे स्वप्रमाणित है कि केन्द्र व राज्य सरकारें स्वयं इस समस्या पर कितनी बहरी, गूंगी और अंधी बनी रही हैं। टीवी चैनलों पर दिल्ली में दस वर्षीय बालक को एक पार्क में कुत्ते द्वारा गंभीर रूप से घायल करने का दृश्य देश भर ने देखा होगा। राज्य व केन्द्र सरकारों को इस देश की कई समस्याओं के प्रति अपनी कुंभकर्णी नींद को त्याग कर उस समस्या का निदान और निराकरण करने की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिये। जिला कलक्टर और एस.पी. को अपने–अपने अधिकार की कानून व्यवस्था, पार्किंग, ट्राफिक, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण, स्वच्छता व कुत्तों आदि अन्य समस्याओं पर संज्ञान, निदान व निराकरण हेतु पाबंद किया जाना चाहिये। संबंधित विभाग के अधिकारी को तुरंत निलम्बित या अभिकरण को भंग करने की सिफारिश भी वे राज्य सरकार से करें तभी समस्याएँ हल होंगी।

–अतिथि सम्पादक,
कैलाश विहारी वाजपेयी,
(स्वतंत्र चिंतक व लेखक)

अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार : उद्यमी

देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और सरकार के बजट को गति देने वाला मुख्य किरदार 'उद्यमी' के लिए हमारे देश में कोई बहुत अच्छी धारण नहीं है। मेरा मानना है, समाज में उद्यमी के लिए इस प्रकार की नकारात्मक सोच न्यायसंगत नहीं है। उद्यमी ही जन–जन की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की प्रतियोगी बाजार में काम करते हुए पूर्ति करता है। उत्पादन और विक्रय की इस प्रक्रिया से ही करोडों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, उन सभी का घर और संसार चल रहा है। मात्र सरकारी नौकरियों के भरोसे देश नहीं चला करते है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मुश्किल से 3 करोड़ लोग सरकारी व्यवस्था में काम कर रहे है। उद्यमी अपने यहाँ अर्थात् निजी क्षेत्र में काम करने वालों को तो वेतन भुगतान करता ही है, साथ–साथ में जी.एस.टी. और आयकर के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पगार की व्यवस्था करता है।

इतना कुछ करने के बावजूद भी उद्यमी की समाज में छवि शोषक की बनी हुई है। हो सकता है कुछ उद्यमियों ने परिस्थिति विशेष का लाभ उठाते हुए खूब लाभ कमाया होगा, कर्मचारियों के वेतन में कंजूसी की होगी, परन्तु इस आधार पर कर्मवीरों की इस पूरी जमात को दोषी नहीं ठहरा सकते है। हमें उद्यमी के आलीशान मकान, बड़ी–बड़ी गाड़ियों और विलासिताओं के पीछे छिपे हुए जोखिम, तनाव, नवाचार और कर्मण्यता को भी देखना होगा। भरपूर लाभ की सम्भावना के साथ–साथ भरपूर नुकसान की सम्भावना भी उतनी ही प्रबल है।

मेरी एक सलाह है कि आलोचना के बजाय उद्यमी के वैभव से प्रेरणा लिजिए और स्वयं भी उद्यमी बनिये, किसने मना किया है। देश में किसी को भी उद्यमी बनने की छुट है। किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और सिफारिश की मजबूरी भी नहीं है। फिर भी आम आदमी उद्यमी नहीं बनना चाहता है क्यों कि वह उद्यमिता के क्षेत्र में भारी मात्रा में उपलब्ध जोखिम व तनाव को झेलने की क्षमता नहीं रखता है। वह अपने कम्फर्ट जॉन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। 24ग7 काम करने की मानसिकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस साहसी उद्यमी की थोड़ी बहुत तारीफ जरूर कीजिये, हो सकता है आपकी तारीफ उसके लिए प्रेरणा का काम करें, वह ओर अच्छे ढंग से समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करें।

उद्यमिता एक नई सोच, नई दिशा में कुछ नया व्यवसाय प्रारम्भ करने की इच्छाशक्ति है। उद्यमिता से लोगों में साहसिक प्रवृति का जन्म होता है। नवाचार एवं सृजनशीलता के प्रति समाज में विश्वास बढ़ ता है। ओयो रूम्स के फाउण्डर रितेश अग्रवाल ने

डॉ. कैलाश सोडाणी

ठीक कहा है कि "जीवन में किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है।" नये विचार को धरातल पर साकार करने का सफर आसान नहीं होता है। बहुत सी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना होगा। निवेशकों और अपने आस–पास के लोगों को अपनी योजना से सहमत करना एक बड़ी चुनौती है। महज 18 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल ने 2013 में आयो रूम्स की स्थापना की और आज कम्पनी से 10,000 से अधिक होटल जुडे हुए है। हजारों करोड़ का व्यवसाय खड़ा हो गया है।

दूसरा उदाहरण ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी का है। जिनका ओला केब की स्थापना के पीछे सोच यह था कि आज के युग में व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के बाद चौथी आवश्यकता ट्रांसपोर्ट की है। ओला की शुरूआत में लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि परिवार ने भी भारी विरोध किया कि अच्छी खासी माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर टैक्सी का धंधा क्यों शुरू करना चाहते हो। परन्तु भविश का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था प्रारम्भ में ग्राहकों के फोन स्वयं अटेण्ड करना, ड्राइवर बनना जैसे छोटे–छोटे काम करते हुए आगे बढ़े। भाविश में काम के प्रति एक जुनून था, जो उसे 24 घण्टे दौड़ने के लिए विवश कर रहा था। मात्र 24 साल की उम्र में भाविश ने ओला केब्स की शुरूआत की थी। 2010 में एक बिल्डिंग के बेसमेन्ट में इस कम्पनी का शुभारम्भ हुआ और आज इसके पास 10 लाख टेक्सीयाँ है, करीब 2 लाख बुकिंग प्रतिदित प्राप्त कर रहे है। रितेश का कहना है कि "दुनियाँ का हर व्यक्ति सपने देखता है पर जो जोखिम उठाता है वहीं सफल होता है।"

जुनून और नवाचार की दुनियाँ के एक ओर शख्स की यहाँ चर्चा करना चाहूंगा और वह है पेटीएम का संस्थापक श्री विजय शेखर शर्मा। विजय के दिमाग में कैशलेस ट्रान्जेक्शन का विचार आया। 2010 में पेटीएम लाँच करके समाज को ऑनलाइन पेमेन्ट, रिचार्ज, बिल पेमेन्ट आदि की सुविधा प्रदान की। पेटीएम के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए रतनटाटा, अलीबाबा जैसों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। 2017 में फोर्ब्स ने विजय शर्मा को भारत का यंगस्टर बिलेनियर घोषित किया।

उद्यमी मोलिक चिंतक और नवप्रवर्तक होता है, जो जोखिम की बाढ़ में अपनी मामूली पूँजी की छोटी सी बोट से अनजानी राहों पर यात्रा प्रारम्भ कर देता है। परिचित राह पर तलवार चमकाने वाले तो कायर होते है। सच्चे अर्थ में उद्यमी कर्मयोगी होता है। जो केवल कर्म में विश्वास करता है, फल अर्थात् लाभ मिलेगा या नहीं, ईश्वर पर छोड़ देता है। उद्यमी अपनी सफलताओं से शर्मिन्दा नहीं होता है, हार नहीं मानता है। अपनी धुन का पक्का खिलाड़ी होता है। उद्यमी सकारात्मक सोच के साथ 365 दिन काम करता है। शनिवार–रविवार उसके शब्दकोष में नहीं होते है।

उद्यमी मूलतः साहसी होता है। बिना किसी डर और भय के कार्य निष्पादित करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ता है। हमें यह सहर्ष स्वीकार करना चाहिये कि उद्यमियों की इन साहसिक गतिविधियों से हमारी सुविधाओं में किस तेजी से विस्तार हो रहा है। उद्यमिता सम्मान का हक रखती है। देश की शैक्षणिक संस्थाओं को नौकरी के इच्छुक प्रत्याशियों के भीड़ की जगह नौकरी देने वाले उद्यमी तैयार करने होंगे। भारत को आधुनिक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता के विचार को प्रतिष्ठा के साथ लोकप्रिय बनाना होगा।

– डॉ. कैलाश सोडाणी
पूर्व कुलपति, एम.डी.एस.
वि.वि., अजमेर

खिलाड़ियों को प्रशासन बांट रहा बैन पॉलिथिन में खाना

बुहाना, (निसं)। पुरानी कहावत है बाबो सैने मारै, बाबा नै कुण मारै...। जो चरितार्थ ना केवल आज के वक्त में भी हो रही है। बल्कि तस्वीरों के सामने सामने भी आ रही है। देशभर में भले ही 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है लेकिन बुहाना में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ियों व ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को खाना प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर दिया जा रहा है । बड़ी बात यह कि प्रशासन ही इस्तेमाल करते दिखे तो कार्रवाई कौन करेगा। जानकारी के अनुसार बुहाना के राजकीय स्कूल खेल मैदान में कबड्डी व खो–खो के मैच खेले जा रहे हैं।

खिलाड़ियों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी बीडीओ कृष्ण कुमार चावला को दी गई है। बुहाना में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। यहां

प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों में खाना खाते ग्रामीण ओलम्पिक के खिलाड़ी।

खिलाड़ियों के लिए खाना प्लास्टिक की थैलियां में पैक होकर आया। संबंधित अधिकारी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने माना कि भोजन की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है लेकिन जब प्लास्टिक थैलियों में खाना पैक के बारे में सवाल किया तो फोन काट दिया। दुबारा फोन करने पर फोन नहीं उठाया।

ये हैं नियम, जो संभवतया प्रशासन पर लागू नहीं होता:- नियमों की बात करें तो प्लास्टिक की थैलियां काफी समय से राजस्थान में बंद है लेकिन हाल ही में इसी साल 1 जुलाई से पूरे देश में ही सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस दौरान अगर कोई प्लास्टिक की थैली में सामान बेचता पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाता है। यदि ग्राहक इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी जुर्माना वसूले जाने के प्रावधान किए गए है। बता दें कि इसके लिए कई विभागों को कार्रवाई के लिए अधिकृत भी किया गया है। लेकिन यहां पर इस्तेमाल करने वाला भी कार्रवाई करने वाले है। तो इन पर कार्रवाई कौन करें। यह सवाल हर किसी के जेहन में गूंज रहा है।

आम शेयरधारकों की समस्या निदान के ठोस सुझाव

अनेक मेरे वरिष्ठ मित्र भौतिक शेयरों को लेकर काफी परेशान हैं। सबसे पहले भौतिक शेयरों से सम्बन्धित पीड़ा को हिन्दी में विस्तार से प्रकाशन जरूरी है इसके बाद हम सभी पीड़ा को प्रधानमन्त्रीजी तक प्रेषित करने की चेष्टा करें।

हम सभी केवल डीमेट के पक्ष में ही नहीं हैं बल्कि चाहते हैं कि सारे भौतिक शेयर डीमेट में परिवर्तित हो जाए। इसके लिये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं कारपोरेट कार्य मन्त्रालय निदान की ब्यवस्था करें।

हमारे राजनीतिक/आर्थिक/ स्टॉक एक्सचेंज विशेषज्ञों की राय पर हम अपनी –अपनी कमाई अनुसार टैक्स चुकाने के बाद जो भी बचत कर पाये उसे शेयरों में लगाया ।

सुरक्षा उद्देश्य के मद्देनजर अपने जीवनसाथी, बेटे, बेटी (जैसा भी मामला हो) के अलावा किसी भी परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त नामों में शेयरों को रखा।

आलेख का एकमात्र उद्देश्य भौतिक शेयरों के हस्तांतरण प्रतिबंध में कुछ छूट की क्यों आवश्यकता है वाले तथ्य की सही स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराना है।

कारपोरेट कार्य मन्त्रालय एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) दोनों ने भौतिक शेयरों के ट्रान्सफर पर पूर्णतया रोक लगा रखी है जिसके चलते छोटे वरिष्ठ शेयरधारकों की समस्या बढ़ गयी।

सभी वरिष्ठ छोटे शेयरधारक अपने शेयर डीमेट कराना चाहते हैं लेकिन वे ऐसा चाहकर भी अपनी अपनी समस्याओं के चलते नहीं कर पा रहे हैं। यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) व कारपोरेट कार्य मन्त्रालय उनकी समस्याओं पर ध्यान दे तब डीमेट प्रक्रिया अवश्य ही गति पकड लेगी। अब पहले उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं पर गौर कर लें......

1) छोटे वरिष्ठ निवेशकों के पास हर समय स्थान परिवर्तन के कारण कम्पनियों के बारे में सही जानकारी का हमेशा ही अभाव रहा है –

क– जिनकी नौकरी ट्रान्सफर होती रहती है उनवे डाक अस्त ब्यस्त होती है जिसके चलते सही जानकारी मिल नहीं पाती।

ख– उसके अलावा काफी कम्पनियां नाम बदल लिया तो कुछ दूसरे में मिल गयीं।

ग– इसके अलावा शेयर के मूल्य में बदलाव भी तकलीफ दे रहा है।

घ– कम्पनियों के पते भी बदल गए या रजिस्ट्रार बदल गए।

च– बहुत सी कम्पनियां बिक भी गयीं तो कुछ प्राइवेट में परिवर्तित हो गयीं।

छ– संयुक्त नाम वाले बेटे/बेटी साथ में नहीं रहते यानि सब अलग–अलग हैं।

2) पति–पत्नी के संयुक्त नाम में शेयर हैं। किसी भी कारणों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं ।

3) अपने पुत्र / पुत्री के साथ संयुक्त नाम से शेयर हैं और पुत्र / पुत्री पढ़ने विदेश गये सो लौट ही नहीं रहे हैं या शादी होने के बाद विदेश गये और वापस लौटना कब होगा अनिश्चित है।

4) पिता / माता की मृत्यु पश्चात बच्चों के संयुक्त नाम में शेयर पर उनके आपसी असहनशीलता के चलते समस्या हो रही है।

5) कुछ ऐसे शेयर भी हैं जिनको डीमेट करवायें तो जो चार्जेज लेगा वो उन शेयरों को बाजार भाव से ज्यादा बैठता है तब इस हालत में बेचने के

गोवर्धनदास बिनानी

समय नुकसान उठाना पडेगा।

6) ऐसी काफी कम्पनियाँ हैं जो शेयर बाजार अर्थात स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर असूचीबद्ध हो गयी जिसके चलते छोटे वरिष्ठ शेयरधारक परेशानी झेल रहे हैं ।

7) असूचीबद्ध कम्पनियों के तो पते मिलना ही एक विकराल समस्या है

8) ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जिन्होंने सेबी के कड़े निर्देश के बाद डीमैट प्रक्रिया शुरू की यानी इससे पहले उनके शेयर डीमैट प्लेटफॉर्म पर थे ही नहीं।

9) अनेक कम्पनी एक ही डिपॉजिटोरी से सम्बन्धित है जिसका मतलब यदि डीमेट अकाउंट उसी डिपॉजिटोरी से सम्बन्धित है तब तो ठीक अन्यथा डीमेट सम्भव नहीं हो पाता है।

ऊपर उल्लेखित कारणों के चलते शेयर बाजार में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के पास अभी भी भौतिक रूप फिजिकल फॉर्म में ही कंपनियों के शेयर पड़े हैं। समाचार पत्रों समय –समय पर जो पढने मिला अनुसार इस समय देश में करीब 2.70 लाख करोड़ रुपये के शेयर भौतिक रूप में हैं। इसलिये सरकार को पहले बुनियादी समस्याओं को हल करना चाहिये अन्यथा कडी मेहनत से किया गया निवेश शून्य में परिवर्तित हो जायेगा ।

समस्याओं के निदान हेतु कुछ सुझाव.......

पहले नाम यानि जिसका नाम प्रथम हो उसे संयुक्त नामों में रखे गए भौतिक शेयरों को अपने नाम में डीमैट की अनुमति दी जाय ।

कारपोरेट कार्य मन्त्रालय के साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेब में सभी कम्पनियों का नाम होना चाहिए यानि जिस नाम से सबसे पहले कम्पनी सूचीबद्ध हुयी उसी से शुरू हो।

अ) ऐफिडेविट प्रक्रिया सादे कागज पर मान्य कर दी जाय जबकि इन्डेमनिटी किसी भी मूल्य के उपलब्ध स्टाम्प पेपर पर।

ब) प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यकता हटा दी जाय यानि सम्बंधित थाने में रजिस्ट्री से सूचना भेजी उसकी स्वहस्ताक्षिरत कापी के साथ रजिस्ट्री की रसीद ले लें।

स) विज्ञापन करने का दायित्व व खर्चा कम्पनीयों पर ही होना चाहिये यानि कम्पनीयां चाहें तो नज़रअंदाज़ भी कर सकें और इस तरह के शेयर भौतिक रूप में जारी ही न किये जाँय बल्कि एक म्यूचूअल फंड की तरह होल्डिंग पत्र जारी कर दे।

द) वरिष्ठों के हस्ताक्षर वाली समस्या का निदान कुछ हद तक किया गया है लेकिन अभी भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ।

ई) छोटे वरिष्ठ शेयरधारकों को अपने संयुक्त धारक से एक बार हस्ताक्षर लेना पडे ताकि वह आसानी से डीमेट प्रक्रिया पूरी कर सके।

सरकार/ सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं ।

इसी तरह और भी समस्यायें हैं उदाहरणार्थ किसी कारण से सात साल यदि डिवीडेंड का या तो पता नहीं चला या डिवीडेंड जमा नहीं कराया तो डिवीडेंड रकम के साथ साथ भौतिक शेयर भी सेबी विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि में सरकार के खाते में जमा हो जाता है भले ही आपके अपने नाम वाले शेयर भौतिक अवस्था में आपके पास रखे हों।

सेबी निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि से क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाया जाना अति आवश्यक है ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं कारपोरेट कार्य मन्त्रालय दोनों ही यदि डीमेट की जिम्मेदारी कम्पनियों पर डाल दें अर्थात जो भी शेयर ट्रान्सफर / ट्रान्समिशन / ट्रान्सपोजिसन के लिये आये तो उन पर कार्यवाही पश्चात डीमेट खाते में ही क्रेडिट दिया जाय तो निश्चित ही बहुत कम समय में काफी संख्या में भौतिक शेयरों से मुक्ती मिल जायेगी । अथवा डीमेट में परिवर्तन हेतु नियमों में कुछ उचित रियायत दे तो डीमेट प्रक्रिया अवश्य ही गति पकड लेगी।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को यह समझना चाहिये कि छोटे वरिष्ठ निवेशक डीमेट कराने की चाहत रखते हुए भी लाचार हैं और समस्याओं का उचित समाधान ही सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करवा देगा ।

मैंने कई साधनों के द्वारा (जैसे-ईमेल, ट्वीटर इत्यादि)अपनी बात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं को पहुँचाने का प्रयास किया है।

–गोवर्धनदास बिनानी
राजा बाबू

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 14 सितम्बर, 2022

आश्विनी मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2079, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 6:57 तक, ध्रुव योग प्रातः 6:17 तक, बालव करण दिन 10:26 तक, चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–मेष, मंगल–वृष, बुध–कन्या, गुरू–मीन, शुक्र–सिंह, शनि–मकर, राहु–मेष, केतु–तुला राशि में।

आज ज्वालामुखी योग दिन 10:26 से आरम्भ होगा। आज पंचमी और भरणी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ–अमृत सूर्योदय से 9:19 तक, शुभ 10:51 से 12:22 तक, चर 3:26 से 4:58 तक, लाभ 4:58 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:15, सूर्यास्त 6:30

मेष
मनः स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। परिवार में चल रहा तनाव दूर होगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

वृष
घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों से मतभेद–अनबन बढ़ने का भय बना रहेगा और समय अनावश्यक खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बढ़ेगा और कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

सिंह
शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। शुभ कार्यों को टालना ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है और अनावश्यक धन खर्च होगा। यात्रा में दुर्घटना का भय बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
घर–परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य आज सुगमता से सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर–परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं और धार्मिक–सामाजिक समारोह में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित और अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और कार्यों से संबंधित जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।